नहीं है। सम्पदा शुल्क अधिनियम 15 अक्तूबर, 1953 से और धन-कर अधिनियम 1 अप्रैल, 1957 से लागू हुआ। 15-10-1953 तथा 1-4-1957 के बाद से जिन व्यक्तियों से सम्पदा शुल्क तथा धन-कर वसूल किया गया उनके नामों तथा प्रत्येक से अलग अलग वसूल की गयी रकम के बारे में सूचना सारे देश में सम्पदा शुल्क के सहायक नियंत्रकों तथा धन-कर अधिकारियों से इकट्ठी करनी पड़ेगी और ऐसा करने में बहुत सा समय तथा श्रम लगेगा। तथापि, इन अधिनियमों के लागू होने के बाद से प्रतिवर्ष पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या, कर और शुल्क सम्बन्धी जारी की गयी मांगों तथा वसूल रकम और वर्ष के अन्त में बकाया रकम के बारे में सूचना विवरण-पत्र में दी गयी है जो सभा पटल पर रखी गयी है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या LT —1933/67]

(ग) बकाया मांग की वसूली के लिए कानून में की गयी व्यवस्था के अनुसार तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये बनारस और एटा जिलों को विश्व बैंक द्वारा ऋण

5601. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के बनारस और एटा जिलों में सिंचाई सुविधायें और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया गया है तथा इस ऋण का केवल इन दोनों जिलों में ही प्रयोग किये जाने का क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, आजकल एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ख) ऋण की रकम के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इस योजना के लिए इन दो जिलों का चुनाव तकनीकी और आर्थिक कारणों से, अर्थात् इस आधार पर किया गया है कि इन जिलों में विविध प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल करने से प्राप्त होने वाला अनुभव उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से में कृषि के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इन समस्याओं का सम्बन्ध राज्य के और गैर-सरकारी क्षेत्र में नलकूपों के विकास और संचालन, विभिन्न प्रकार की चट्टानी जमीनों में छेद करने, विभिन्न प्रकार के ऋण-संगठनों, जैसे सहकारी, सरकारी और वाणिज्यिक बैंकों के आपसी सम्बन्धों, जमीन की किस्मों और खारेपन आदि से है।

मूल्य सूचकांक

5602. **श्री ब्रह्मानन्द जी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1967 से जून, 1967 की अवधि में मूल्य सूचकांक प्रतिमास क्या रहा है और गत 12 महीनों का औसत सूचकांक क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के मूल्य सूचकांक को प्रसारित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मांगी गयी सूचना नीचे सारणी में दी गयी है :

थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक
(आधार : 1952–53 –100)

फरवरी, 1967	203.0
मार्च, 1967	203.4
अप्रैल, 1967	204.3
मई, 1967	208.3
जून, 1967	214.1
जुलाई, 1966 से जून, 1967 तक का औसत	198.1

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सूचक अंक औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मंत्रालय के आर्थिक परामर्शदाता के कार्यालय द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है और आर्थिक पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचारपत्रों आदि द्वारा भी सूचित किया जाता है]

Black-marketing in Newsprint

5603. Shri George Fernandes:
Shri Madhu Limaye:
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the blackmarket transactions in newsprint indulged in by the New Prabhat Publications, Ahmedabad which were facilitated by large newsprint quota obtained on the basis of bogus newspapers and bogus circulation figures;

(b) the Income-tax paid by this concern during the last 10 years or since its foundation, whichever period is less;

(c) whether their income has been reassessed in view of the information about blackmarket transactions and manipulation of account books; and

(d) if so, the income reassessed and the tax imposed thereon?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) **Year-wise figures of** tax pa are as follows:—

1955-56	Rs. 1,871
1957-58	Rs. 1,853
1958-59	Rs. 1,673
1960-61	Rs. 2,990
1961-62	Rs. 11,004

The assessment for assessment year 1962-63 has been completed on a total income of Rs. 1,65,300/- as against returned income of Rs. 26,257/-. The assessee has filed an appeal before the Appellate Assistant Commissioner. Assessments for subsequent years are pending.

(c) No assessment has yet been reopened. Investigations are still in progress.

(d) Does not arise.

Foreign Aid

5604. Shri G. S. Mishra:
Shri G. C. Dixit:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total aid that was required to complete the annual plan 1966-67;

(b) the total amount received from:

(1) Aid India Club;
(2) Anglo Indian Consortium;
(3) U.S. Aid;
(4) World Bank;
(5) East European Countries;
(6) U.S.S.R.; and
(7) Other Sources; and

(c) whether this aid was sufficient to meet the total requirements?